

**Title:** Requested the Government to present a report regarding the Government's handling of the cases of corruption in the bureaucracy.

**श्री विजय गोयल :** अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की ओर दिलाना चाहता हूँ कि आपने पिछले समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा कि डीडीए के वाइस-चेयरमैन के पी.एस. के पास से करोड़ों रुपया मिला है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि सेल्स टैक्स के दो ऑफिसर्स को अभी पकड़ा गया था और पिछले दिनों एक्सम्युनिसिपल कमिश्नर के यहां छापा पड़ा जिसमें करोड़ों रुपया मिला।

करप्शन का फिनॉमिना आज का नहीं है। यह वॉ से देश के अंदर है और 1947 के बाद से लगातार इस देश में चलता आ रहा है किंतु इस पर रोक नहीं लगी है, यह कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि जगह-जगह पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो अधिकारी पोस्ट होते हैं, वे हर चौथे दिन दिल्ली के अंदर किसी न किसी बहाने से आए हुए होते हैं। अगर सरकार उनके बिल्स निकालकर देखे कि जो आदमी नॉर्थ ईस्ट में या दूसरे एरियाज में पोस्ट होते हैं, हर महीने में वे कितने चक्कर लगा रहे हैं? (व्यवधान) हिमाचल में या दूसरी जगह में भी जो लोग पोस्ट होते हैं, (व्यवधान)

**श्रीमती रेणुका चौधरी (खम्मम) :** अर्बन एरियाज में जितनी प्राइम लैंड है या सोसाइटीज की लैंड है, वह सब उन्हीं के पास है। (व्यवधान)

**श्री विजय गोयल :** अभी यह बता रही हैं कि अर्बन एरियाज में जितनी प्राइम लैंड है या सोसाइटीज की लैंड है, ज्यादातर इन्हीं लोगों के पास है। अभी डिसकशन हो रहा था कि सबसे ज्यादा करप्शन कहां पर है, पोलिटिशियन में हैं या ब्यूरोक्रेट्स में है या ज्युडिशियरी के अंदर है? मैं हमेशा कहता हूँ कि पोलिटिशियन तो दस प्रतिशत भी करप्ट नहीं होंगे। बाकी विभागों में आप जाकर देखेंगे कि 90 प्रतिशत तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। (व्यवधान) आम आदमी के काम होने बंद हो गये हैं। हर काम घूस से होता है तो आम आदमी का काम कौन करेगा? इस बारे में ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए सरकार को टाइम लिमिट फिक्स करनी चाहिए कि इतने दिनों के अंदर इस काम को पूरा किया जाएगा। (व्यवधान) मेरा राजनैतिक दलों से भी कहना है कि पोलिटिशियन्स की छवि को सुधारने के लिए एक बार सब दलों के लोगों को एक साथ बैठना चाहिए। टी.वी. जो मर्जी पर शेखर सुमन कहता रहता है और जो मर्जी दूसरे कार्यक्रमों में भी आता रहता है। आपने देखा होगा कि रेल का भी 'आज तक' में एडवर्टाइजमेंट चलता है। जगह-जगह पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। अब सरकार या तो इसके लिए विशेष आयोग बनाए क्योंकि आज यदि आप किसी बड़े अफसर के यहां जो पब्लिक डीलिंग में है, यदि छापा मारकर देख लीजिए तो 99 प्रतिशत मामलों में आपको लगेगा कि कुछ न कुछ दाल के अंदर काला है।

सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग भ्रष्टाचार में पकड़े गए हैं या जिन लोगों के यहां छापे पड़े हैं, इस घटना के बाद उनकी सिर्फ दूसरी जगह नियुक्ति हो जाती है। लेकिन अगर एक एमपी काम नहीं करेगा, तो पांच साल या दो साल के बाद अपने आप चला जाएगा, लेकिन ब्यूरोक्रेट के यहां भ्रष्टाचार फैला रहता है। ब्यूरोक्रेट काम करे या न करे, ज्यादा से ज्यादा उसकी तबदीली हो जाएगी। हम सब लोगों को इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि इस विषय पर आधे घण्टे की चर्चा कराई जाए, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग भाग ले सकें। (व्यवधान) नियम 193 के अन्दर भी चर्चा कराई जा सकती है।

अंत में, मैं एक निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा। क्या किसी आफिसर के पीएस के पास करोड़ों रुपए मिलें, तो उस आफिसर की रिसपांसिबिलिटी इसलिए नहीं मानी जाएगी कि वह तो मेरा पीएस लेता था। मेरा सरकार से निवेदन है कि जहां-जहां भी छापे पड़े हैं और भ्रष्टाचार के मामले पकड़े गए हैं, उन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है, उसकी रिपोर्ट सदन में उपस्थित करने का आश्वासन मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।